रविवार, 1 फरवरी, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

टेम्बा बावुमा के बयान से गौतम गंभीर को मिला समर्थन

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

साई पल्लवी को तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार बेस्ट अभिनेत्री का सम्मान

Page-05

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा- अजित दादा के सपनों को करेंगी साकार

महाराष्ट्र की राजनीति में ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के 4 दिनों बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. मुंबई के लोक भवन में आयोजित शपथग्रहण समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें शपथ दिलाई. इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे. सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी.प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने वाली सुनेत्रा पवार को हार्दिक शुभकामनाएं. वह इस पद को संभालने वाली पहली महिला हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि वह राज्य की जनता के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और दिवंगत अजित दादा पवार के सपनों को साकार करेंगी.

2. 25 मौतें, मालिक फरार—आनंदपुर आग पर शाह का वार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कोलकाता के आनंदपुर इलाके में हुई भीषण आग की घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. अमित शाह ने कहा कि वाओ मोमो के फैक्ट्री-कम-वेयरहाउस में लगी आग कोई साधारण हादसा नहीं थी, बल्कि यह राज्य प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार का नतीजा है. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. बैरकपुर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद फैक्ट्री मालिक की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना कई सवाल खड़े करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिक सत्ता में बैठे लोगों के बेहद करीब है, इसी वजह से उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही.

भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबला, सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को दिया जीत का गुरुमंत्र

U19 विश्व कप 2026 अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है. रविवार को बुलावायो के मैदान पर क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, भारत बनाम पाकिस्तान. यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि सेमीफाइनल का टिकट पाने की आखिरी जंग है.एक तरफ ग्रुप-1 से ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान पहले ही अंतिम चार में जगह बना चुके हैं, वहीं ग्रुप-2 से इंग्लैंड ने अपना स्थान पक्का कर लिया है.

इतिहास रचा गया:

आंसुओं के बीच सुनेत्रा पवार ने संभाला उप-मुख्यमंत्री पद

सियासत में ऐतिहासिक दिन: सुनेत्रा पवार ने ली उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ

महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के चौथे दिन सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहला डिप्टी सीएम बन गईं हैं. उन्हें महाराष्ट्र के लोकभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई. यह शपथग्रहण समारोह लगभग 12 मिनट तक चला. महाराष्ट्र विधान परिषद की डिप्टी चेयरपर्सन डॉ नीलम गोर्हे शपथ ग्रहण समारोह तक सुनेत्रा पवार को ले गईं. शपथग्रहण समारोह से एक दिन पहले NCP के विधायक दल और विधान परिषद के सदस्यों की विधान भवन में बैठक हुई थी. जिसमें सुनेत्रा पवार को पार्टी का नेता चुना गया था. डिप्टी सीएम बनने से पहले सुनेत्रा राज्यसभा सांसद थीं. उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. बता दें कि 28 जनवरी को महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की बारामती में प्लेन हादसे में मौत हो गई थी.दादा अजित पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के प्रचार के लिए जा रहे थे. उन्हें 4 रैलियों को संबोधित करना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. उनके आकस्मिक निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया. जिस दौरान राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और कोई भी सरकारी मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा.

पश्चिम एशिया संकट:

मोदी से मिले अरब मंत्री, नेतन्याहू ने रद्द किया दौरा

ईरान और अमेरिका के बीच उफनते तनाव ने पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। इसी पृष्ठभूमि में भारत में अरब देशों के विदेश मंत्रियों का एकजुट होना शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला संदेश है। भारत और अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अरब प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली आज पश्चिम एशिया की राजनीति में एक निर्णायक केंद्र बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरब प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए भारत और अरब जगत के बीच सदियों पुराने जन संपर्क संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यही ऐतिहासिक जुड़ाव आज व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और नवाचार के नए अध्याय खोलने की बुनियाद है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान उस समय आया जब पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की आशंकाएं गहराती जा रही हैं और वैश्विक शक्तियां अपनी अपनी चालें चल रही हैं।

हलवा सेरेमनी के बाद

क्यों 'लॉक' हो जाती है बजट टीम?

1 फरवरी को वित्त मंत्री भारत का केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. जिसकी औपचारिक शुरुआत 27 जनवरी को हुई हलवा सेरेमनी के साथ हो चुकी है. बजट से ठीक पहले नॉर्थ ब्लॉक में होने वाली यह हलवा सेरेमनी (Halwa Ceremony) हर साल सुर्खियां बटोरती है. बता दें कि यह आयोजन देखने में सरल लगता है लेकिन इसका गहरा महत्व है. यह बजट तैयार करने के अंतिम चरण, दस्तावेजों की गोपनीयता और छपाई की शुरुआत का प्रतीक है. वहीं इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नॉर्थ ब्लॉक में होने वाले इस समारोह में हिस्सा लिया था. दरअसल, हर साल संसद में केंद्रीय बजट पेश होने से कुछ ही दिन पहले, नई दिल्ली स्थित वित्त मंत्रालय के अंदर एक अनोखी रस्म अदा की जाती है. जिसे हलवा समारोह के नाम से जाना जाता है. बताते चलें कि ये परंपरा बजट तैयार करने के अंतिम चरण और बजट दस्तावेजों के प्रति कड़ी गोपनीयता की शुरुआत का प्रतीक होती है.

बड़ा निर्णय: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बदलेगी लड़कियों की तस्वीर

पीरियड्स को लेकर समाज की सोच बदली है लेकिन आज भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। स्कूलों में आज भी छात्राओं को झिझक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस दौरान आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स के दौरान छात्राओं को क्लास तक छोड़नी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म के दौरान साफ और सुरक्षित साधनों की कमी एक बच्ची की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मासिक धर्म से जुड़ा स्वास्थ्य अधिकार भी शामिल है। सुरक्षित सुविधाएं न मिलने पर कई बच्चियां स्कूल नहीं जा पातीं या असुरक्षित तरीके अपनाती हैं। इससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा, पीरियड किसी वाक्य को खत्म करने के लिए हो न कि लड़कियों की स्कूली शिक्षा। मासिक धर्म सामग्री की कमी, स्कूलों में लड़कियों की समान भागीदारी को असंभव बना देती है, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में भागीदारी प्रभावित होती है। शिक्षा का अधिकार एक 'गुणक अधिकार' है, जो अन्य मानवाधिकारों के प्रयोग को संभव बनाता है। फ्री शिक्षा में वे सभी खर्च शामिल है जो किसी बच्चे को शिक्षा पूरी करने से रोकते हैं।

आवश्यकता

Tv भारतवर्ष ग्रुप

को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में e रिपोर्टर की। और पॉडकास्ट हेतु टैलेंटेड युवक ,और युवतियों की जो डिजिटल मीडिया में अपना भविष्य और पहचान बनाना चाहते है ।

इच्छुक अभ्यर्थी अपनी सीवी 8601780000 व्हाट्सप्प के माध्यम से भेंजे

भारत-अरब लीग की बैठक में बोले जयशंकर

हम ऐसे मोड़ पर मिल रहे हैं जब ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा,

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को भारत-अरब लीग की विदेश मंत्री स्तरीय दूसरी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व में कई बदलाव हो रहे हैं, जिसका असर हम सब पर पड़ा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में पश्चिम एशिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनमें से कई का असर इस क्षेत्र से कहीं ज्यादा दूर तक हुआ है।

भारत-अरब लीग की विदेश मंत्री स्तरीय दूसरी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, "हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर मिल रहे हैं जब कई कारणों से ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव हो रहा है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और डेमोग्राफी, ये सभी पूरी तरह से सक्रिय हैं। पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व में यह सबसे ज्यादा साफ दिखता है, जहां पिछले एक साल में हालात में जबरदस्त बदलाव आया है। इसका असर हम सभी पर पड़ता है, जिसमें भारत भी शामिल है क्योंकि यह एक पड़ोसी क्षेत्र है।"

उन्होंने कहा कि विकसित भारत का अर्थ सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण कैसा हो, ये भी विकसित भारत का महत्वपूर्ण पहलू है। एक नागरिक के रूप में हमें अपने कर्तव्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है। जयशंकर ने कहा, "काफी हद तक, इसके नतीजे भारत के अरब देशों के साथ संबंधों के लिए भी प्रासंगिक हैं। पिछले कुछ सालों में पश्चिम एशिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनमें से कई का असर इस क्षेत्र से कहीं ज्यादा दूर तक हुआ है। खासकर गाजा की स्थिति अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चर्चा का केंद्र रही है। हममें से कई लोग अक्टूबर 2025 में शर्म अल-शेख शांति शिखर सम्मेलन में मौजूद थे, जो नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 में बदल गया।" बता दें कि भारत-अरब लीग की विदेश मंत्री स्तरीय दूसरी बैठक की भारत मेजबानी कर रहा है। इसके लिए 20 से अधिक देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। इस बैठक के शुरू होने से पहले जयशंकर ने कोमोरोस, लीबिया, सोमालिया और फिलिस्तीन के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को भारत-अरब लीग की विदेश मंत्री स्तरीय दूसरी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व में कई बदलाव हो रहे हैं, जिसका असर हम सब पर पड़ा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में पश्चिम एशिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनमें से कई का असर इस क्षेत्र से कहीं ज्यादा दूर तक हुआ है।

ट्रंप के निमंत्रण को लेकर न्यूज़ीलैंड का साफ इनकार, कौन देश साथ और कौन खिलाफ?

न्यूज़ीलैंड का कहना है कि वह डोनाल्ड ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने का न्योता स्वीकार नहीं करेगा. देश के विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर "स्पष्टता" की मांग की है. ट्रंप का कहना है कि इसका मक़सद ग़ज़ा में इसराइल और हमास के बीच संघर्षविराम को स्थायी बनाना और फ़लस्तीनी क्षेत्र में एक अंतरिम सरकार की निगरानी करना है. इससे पहले ट्रंप ने कनाडा को दिया न्योता ख़ुद वापस ले लिया था क्योंकि दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर मुखर भाषण दिया था. बोर्ड ऑफ़ पीस की अध्यक्षता ट्रंप खुद कर रहे हैं और शुरुआत में इसकी रूपरेखा, ग़ज़ा के भविष्य को लेकर उनकी योजना की निगरानी के लिए कुछ चुनिंदा वैश्विक नेताओं के समूह के रूप में तय की गई थी. लेकिन ट्रंप की महत्वाकांक्षा आगे बढ़ती गई और अब इसे दुनिया भर के संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका देने की बात कही जाने लगी. इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका को पीछे छोड़ने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे कई देश सतर्क रुख़ अपना रहे हैं.

आज पेश होगा बजट 2026,

सरकार के बड़े ऐलानों पर टिकी निगाहें

बजट 2026 से मध्यम वर्ग को टैक्स राहत की उम्मीद, स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन पर नजर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यानी 1 फरवरी, रविवार को सुबह 11 बजे अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। साल 2017 में बजट की तारीख बदलने के बाद यह पहला मौका है जब रविवार को बजट पेश किया जा रहा है। बाजार की अहमियत को देखते हुए BSE और NSE ने विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित करने का फैसला किया है। वहीं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, भारत बजट 2025 में किए गए ऐतिहासिक बदलावों के बाद, निर्धारण वर्ष 2025–26 से नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब को अधिक तर्कसंगत बनाया गया था। फिलहाल 4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, जबकि 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 लाख से 12 लाख पर 10%, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 लाख से 20 लाख पर 20%, 20 लाख से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स देय है। विशेष बात यह है कि धारा 87A के तहत 60,000 की बढ़ी हुई छूट के कारण अब 12 लाख तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले

निवासियों को कोई आयकर नहीं देना होता है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर, प्रभावी रूप से 12.75 लाख तक की सालाना आय पूरी तरह टैक्स-फ्री है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम आगामी बजट 2026 से घरेलू जोखिम पूंजी के प्रवाह को सुगम बनाने और नियामक बाधाओं को कम करने की उम्मीद कर रहा है। SEBI के कड़े मानदंडों के बाद एंजेल फंडिंग में आई गिरावट को देखते हुए, विशेषज्ञ एंजेल टैक्स नियमों में और ढील देने और फैमिली ऑफिसों के लिए निवेश के लचीले विकल्पों की मांग कर रहे है।

दुश्मन के फाइटर जेट्स के लिए काल बनी आकाश NG, DRDO की स्वदेशी मिसाइल की बड़ी कामयाबी

अमेरिका-ईरान में बढ़ते तनाव के बीच कई देशों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में भारत भी लगातार अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में डीआरडीओ की स्वदेशी मिसाइल तकनीक आकाश-एनजी को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। आकाश नेक्स्ट जेन मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया है। इसका मतलब है कि ये स्वदेशी मिसाइल 50 किलोमीटर तक टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सफल साबित हुई। डीआरडीओ के आकाश एनजी मिसाइल की मारक क्षमता में इजाफा नए डुअल-पल्स मोटर की सफल टेस्टिंग के बाद मिली है। इस नई तकनीक से अब यह मिसाइल दुश्मनों के फाइटर जेट को लेकर और भी खतरनाक हो गई है। अब ये हवाई खतरों को आसानी से टारगेट करने में सक्षम होगी। आर्म्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के प्रमुख अंकाथी राजू ने बताया कि इन टेस्ट के बाद सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइलें रडार पर आसानी से पकड़ में नहीं आएंगीं। इससे पहले आकाश मिसाइलों में रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता था। हालांकि, नई आकाश-नेक्स्ट जेन में एक खास डुअल-पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगाई गई है। यह मोटर दो अलग-अलग फेज में थ्रस्ट पैदा करती है। ARDE अधिकारियों के अनुसार, इससे मिसाइल एक्शन के दौरान और भी तेज रफ्तार और बेहतर दांव से कार्रवाई में सक्षम है। आकाश एनजी की मारक क्षमता में इजाफे से अब ये लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और तेज रफ्तार वाले ड्रोनों को भी आसानी से निशाना बना सकती है। ये ऐसे टारगेट होते हैं जिन्हें पुराने एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाते थे। इस मिसाइल की रेंज में सबसे बड़ा सुधार इसके प्रोपल्शन सिस्टम में किए गए बदलावों की वजह से हुआ है।

सिलीगुड़ी से अमित शाह का सख्त संदेश, बोले—घुसपैठ रोकनी है तो TMC सरकार हटे

पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है. इस चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. बीजेपी टीएमसी को हटाने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटा है. वहीं, ममता सरकार पर लगातार केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते आ रही है. इन आरोप-प्रत्यारोप के दौर के बीच शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिलिगुड़ी की यात्रा पर हैं. यहां अमित शाह ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि ममता बनर्जी सरकार की विदाई का समय अब नजदीक है. पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन निश्चित है और जनता बदलाव की उम्मीद रखती है. अमित शाह ने अपने भाषण में ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने अलग-अलग समुदायों को आपस में लड़ाने वाली राजनीति की है, जिससे राज्य की एकता खतरे में पड़ गई

है. उन्होंने बताया कि लंबे समय से पश्चिम बंगाल में सामाजिक तनाव को बढ़ावा दिया गया है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में दूरी बढ़ी है. इस दौरान अमित शाह ने BJP के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे संगठन को मजबूत करें और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर लोगों से जुड़ें. उनका कहना था कि केवल कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव संभव हो सकेगा. उन्होंने कहा कि जनता अब ममता सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है और वह बदलाव चाहती है.

संपादक की कलम से

महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा है, वह है सुनेत्रा पवार। उनके संभावित राजनीतिक उभार को लेकर जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, उसने सत्ता, संगठन और नेतृत्व की दिशा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह एक नए दौर की शुरुआत है, या फिर राज्य की राजनीति में परिवार आधारित नेतृत्व की परंपरा का ही विस्तार?महाराष्ट्र लंबे समय से ऐसे राजनीतिक परिदृश्य का साक्षी रहा है जहाँ बड़े नेताओं की विरासत अक्सर उनके परिवार के सदस्यों तक पहुँचती रही है। इस संदर्भ में सुनेत्रा पवार का आगे आना कुछ लोगों के लिए स्वाभाविक राजनीतिक निरंतरता माना जा सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए यह एक भावनात्मक जुड़ाव का विषय भी है, क्योंकि वे इसे एक ऐसे नेतृत्व के रूप में देखते हैं जो संगठन की पहचान और परंपरा को बनाए रख सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या नेतृत्व केवल पारिवारिक संबंधों के आधार पर तय होना चाहिए, या फिर योग्यता, अनुभव और जनसमर्थन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।इस घटनाक्रम का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि इससे राज्य की राजनीति में महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलने की संभावना है। यदि सुनेत्रा पवार सक्रिय भूमिका निभाती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी करती हैं, तो यह महाराष्ट्र की सत्ता संरचना में महिलाओं की उपस्थिति को मजबूत कर सकता है। हालांकि, केवल पद पर बैठना पर्याप्त नहीं होता; वास्तविक बदलाव तब दिखता है जब नेतृत्व नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार और जनहित के मुद्दों पर ठोस पहल करे।राजनीतिक दृष्टि से यह बदलाव केवल एक व्यक्ति के उभार तक सीमित नहीं रहेगा। महाराष्ट्र की गठबंधन राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन का असर सहयोगी दलों और विपक्ष दोनों पर पड़ता है। यदि यह निर्णय संतुलित तरीके से लिया गया और संगठन के भीतर व्यापक सहमति बनी, तो यह स्थिरता ला सकता है। लेकिन यदि इसे केवल शक्ति संतुलन साधने का कदम माना गया, तो भविष्य में आंतरिक असंतोष और राजनीतिक खींचतान भी बढ़ सकती है।जनता के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा सवाल नेतृत्व की पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि उसका प्रदर्शन होता है। राज्य आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है — जैसे बेरोज़गारी, किसानों की समस्याएँ, शहरी बुनियादी ढाँचे का दबाव और युवाओं के लिए अवसरों की कमी — उनका समाधान ही किसी भी नए नेतृत्व की असली परीक्षा होगा। यदि सुनेत्रा पवार इन मुद्दों पर स्पष्ट दृष्टि और ठोस कार्ययोजना के साथ आगे आती हैं, तो उनका उभार एक सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है।अंततः, सुनेत्रा पवार का संभावित "राजतिलक" केवल एक औपचारिक राजनीतिक घटना नहीं है। यह उस दिशा का संकेत है जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति आगे बढ़ सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव राज्य को नई ऊर्जा और दृष्टि देता है या फिर परंपरागत राजनीति की सीमाओं में ही सिमट कर रह जाता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय हमेशा जनता के हाथ में होता है, और वही तय करेगी कि यह नया अध्याय उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं।

सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली

राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने शनिवार शाम को महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उन्होंने अपने पति और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की जगह ली है, जिनका दो दिन पहले एक विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था. मुंबई के लोक भवन में आयोजित इस गरिमामय समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे. इससे पहले, दोपहर को एक बैठक में सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया था. यह फैसला दक्षिण मुंबई के विधान भवन परिसर में हुई एक अहम बैठक में लिया गया. इस दौरान वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन छगन भुजबल ने किया. अजित पवार के आकस्मिक निधन के तीन दिन बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है. विधान भवन के उसी ऑफिस में यह बैठक हुई जहां कभी अजित पवार बैठा करते थे. बैठक की शुरुआत में सुनेत्रा पवार ने अपने दिवंगत पति की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की. इस मौके पर उनके छोटे बेटे जय पवार भी मौजूद रहे. बैठक का माहौल काफी गमगीन था और कई मंत्री व विधायक अपने आंसू नहीं रोक पाए. इस बीच, एनसीपी (एसपी) चीफ शरद पवार के एक बयान ने सबको चौंका दिया है. उन्होंने बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण की कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने मीडिया से कहा, 'हमें इस बारे में खबरों से पता चला. उनके दल ने क्या फैसला लिया, इसमें हमारी कोई सलाह नहीं ली गई.' शरद पवार ने यह भी दावा किया कि अजित पवार दोनों गुटों के विलय के पक्ष में थे. उनके मुताबिक 12 फरवरी को पार्टी के एक होने का एलान होना था, लेकिन विमान हादसे ने सब बदल दिया. अजित की इच्छा थी कि दोनों राष्ट्रवादी गुट एक साथ आएं और मेरी भी यही इच्छा है."

हालांकि उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री पद को लेकर अभी क्या हो रहा है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है. कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई सवाल नहीं है और कोई चर्चा नहीं है.

UGC कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, UP में फैसले का मिला-जुला असर

लखनऊ: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC-यूजीसी) के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक लगते ही उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। किसी कैंपस में इसे छात्रों की जीत मानकर जश्न मनाया जा रहा है, तो कहीं इसे शिक्षा सुधार की रफ्तार पर ब्रेक बताकर मायूसी छाई हुई है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, नोएडा से गाजियाबाद तक कोर्ट के इस फैसले ने यूपी के छात्रों, विश्वविद्यालय प्रशासन को दो हिस्सों में बांट दिया है।

एक ओर राहत की सांस है, वहीं दूसरी ओर भविष्य को लेकर असमंजस भी गहराता दिख रहा है। बता दें कि इससे पहले सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी इस पूरे मामले पर विरोध जताया था। साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा था। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इसे कारण बताकर इस्तीफा तक दे दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राजधानी लखनऊ में सवर्ण वर्ग के छात्रों ने खुलकर जश्न मनाया गया। हजरतगंज चौराहे पर छात्रों ने एकजुट होकर लड्डू बांटे, नारे लगाए और पोस्टर के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। पोस्टरों पर लिखे नारों तिलक, तराजू और तलवार, नहीं सहेंगे अत्याचार ने आंदोलन के तेवर साफ दिखाए। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताते हुए कहा कि यह संघर्ष की पहली सफलता है, अधिकारों की रक्षा के लिए आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ और आगरा जैसे प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में दिनभर इस फैसले को लेकर चर्चा होती रही। लखनऊ विश्वविद्यालय और डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसे अपनी लंबी लड़ाई का परिणाम बताया है। छात्र संगठनों का कहना है कि UGC के नए नियम लागू होने से प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण व्यवस्था और पाठ्यक्रम संरचना पर नकारात्मक असर पड़ता, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र समूहों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। छात्र नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक ने यह साफ कर दिया है कि बिना व्यापक परामर्श के नियम लागू नहीं किए जा सकते। वहीं, वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में भी कई छात्र संगठनों ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत बताया। हालांकि, हर जगह जश्न का माहौल नहीं है। कुछ शिक्षक संगठनों और विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि UGC

के नए नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाना था। मेरठ- गोरखपुर के कुछ कॉलेजों के प्राचार्यों ने कहा कि बार-बार नियमों पर रोक से शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित होता है, वहीं असमंजस की स्थिति बनती है। उनका कहना है कि सुधार जरूरी हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी उतने ही जरूरी हैं। वहीं गुरुवार सुबह नोएडा सिटीजन फोरम (एनसीएफ) ने कार्यकारी अध्यक्ष शालिनी सिंह के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की हालिया प्रस्तावित गाइडलाइन पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई।

शरद पवार का दावा: अजित चाहते थे दोनों NCP एक हों

महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर शरद पवार ने शनिवार को कहा, 'यह अजित पवार की भी इच्छा थी। इसे जरूर पूरा होना चाहिए।' शरद ने कहा कि अजित, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को विलय का ऐलान होना था लेकिन दुर्भाग्य से, अजित उससे पहले हमें छोड़कर चले गए।

सूत्रों के मुताबिक अजित ने 17 जनवरी को बारामती में शरद पवार से मुलाकात की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विलय पर चर्चा हुई थी। इस मीटिंग का वीडियो भी सामने आया है। इस मुलाकात के 11 दिन बाद अजित की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। उधर शरद पवार के बारामती घर पर शनिवार सुबह पवार परिवार की बैठक हुई। इस बैठक में सुप्रिया सुले, रोहित पवार, युगेन्द्र पवार और शरद पवार शामिल हैं। इसके अलावा शरद गुट के नेता भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं।

अजित के निधन के बाद अब लगभग यह तय है कि महाराष्ट्र का वित्त विभाग फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा और मार्च में CM ही महाराष्ट्र का बजट पेश करेंगे। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब उपमुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के पास गृह और वित्त दोनों महत्वपूर्ण विभाग थे। फडणवीस ने 9 मार्च 2023 को महाराष्ट्र राज्य का बजट भी पेश किया था। जुलाई 2023 में जब अजित पवार महायुति सरकार में शामिल हुए तब वित्त मंत्रालय फडणवीस ने अजित पवार को सौंप दिया था। वे 23 फरवरी को राज्य का बजट पेश करने वाले थे। फडणवीस के पहले कार्यकाल (2014-2019) में वित्त मंत्रालय सुधीर मुनगंटीवार के पास था।

सुधीर मुनगंटीवार अभी सिर्फ विधायक हैं, फडणवीस सरकार का हिस्सा नहीं है। उनके मंत्री बनने और फिर से वित्त मंत्रालय मिलने की संभावना बेहद कम है।

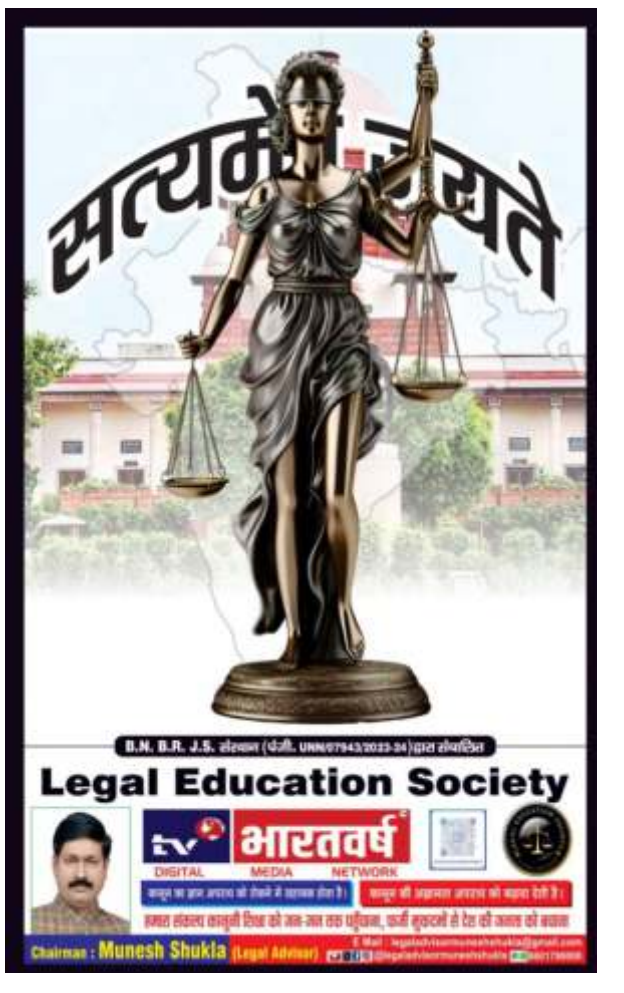

घर बैठे नाम, पता और मोबाइल नंबर बदलना होगा आसान

नया आधार ऐप लॉन्च

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नया आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे देशभर के आधार धारक अब अपनी पहचान से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ घर बैठे स्मार्टफोन के माध्यम से अपडेट कर सकेंगे। यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है और इसका उद्देश्य आधार सेवा केंद्रों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना है।नए ऐप की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि उपयोगकर्ता अब मोबाइल नंबर और पता जैसी जानकारियाँ सीधे ऐप के जरिए अपडेट कर सकते हैं। पहले इन बदलावों के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना जरूरी होता था, लेकिन अब डिजिटल प्रक्रिया के जरिए यह काम अधिक सरल बना दिया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार होगी जिनका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या जो हाल ही में नए पते पर शिफ्ट हुए हैं।ऐप में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। उपयोगकर्ता अब अपनी पूरी आधार डिटेल साझा करने के बजाय केवल जरूरी जानकारी ही डिजिटल तरीके से साझा कर सकते हैं। इसमें सुरक्षित क्यूआर कोड आधारित सत्यापन और सीमित जानकारी साझा करने जैसी सुविधाएँ शामिल की गई हैं, जिससे पहचान के दुरुपयोग की आशंका कम होती है। अधिकारियों का कहना है कि यह फीचर होटल चेक-इन, यात्रा या अन्य पहचान सत्यापन स्थितियों में काफी उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा ऐप में ऑफलाइन आधार सत्यापन की सुविधा भी दी गई है, जिससे इंटरनेट कनेक्शन कमजोर होने की स्थिति में भी पहचान प्रमाणित की जा सकेगी। उपयोगकर्ता अपने परिवार के सदस्यों की आधार प्रोफाइल को एक ही ऐप में प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे परिवार स्तर पर दस्तावेज़ प्रबंधन आसान होगा। यह सुविधा बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी मानी जा रही है। डिजिटल विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था को और मजबूत करेगा और सरकारी सेवाओं, बैंकिंग, मोबाइल सिम सत्यापन तथा अन्य ऑनलाइन सेवाओं में आधार के उपयोग को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगा। साथ ही, सरकार का मानना है कि आधार से जुड़ी सेवाओं का मोबाइल प्लेटफॉर्म पर विस्तार होने से बैंकिंग, सरकारी सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति और मोबाइल सिम सत्यापन जैसी सेवाओं में पारदर्शिता और गति आएगी। डिजिटल पहचान प्रणाली के इस नए चरण को नागरिकों और प्रशासन के बीच भरोसे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एलेना र्यबाकिना बनीं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की चैम्पियन

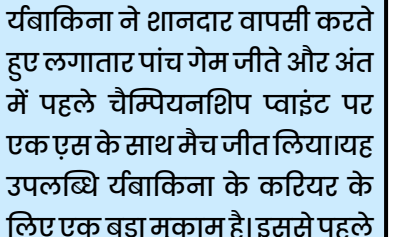

कजाखस्तानी टेनिस स्टार एलेना र्यबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने विश्व नंबर 1 एरीना सबालेन्का को 6-4, 4-6, 6-4 से हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और दूसरी ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी अपने नाम की।फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा, जिसमें र्यबाकिना ने पहले सेट में बढ़त बनाई, लेकिन सबालेन्का ने दूसरे सेट में बराबरी कर मैच निर्णायक सेट तक ले गई। निर्णायक सेट के दौरान सबालेन्का 3-0 की बढ़त ले चुकी थीं, लेकिन र्यबाकिना ने शानदार वापसी करते हुए लगातार पांच गेम जीते और अंत में पहले चैम्पियनशिप प्वाइंट पर एक एस के साथ मैच जीत लिया।यह उपलब्धि र्यबाकिना के करियर के लिए एक बड़ा मुकाम है। इससे पहले उन्होंने विंबलडन 2022 का खिताब जीता था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में यह उनका पहला खिताबी सफर रहा। 26 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी कड़ी मेहनत, संयम और दवाब में शांत प्रदर्शन से ग्लोबल टेनिस समुदाय में अपनी पहचान और मजबूत की है।

ऑस्ट्रेलियन ओपन फ़ाइनल: जोकोविच और अल्कारेज़ के बीच खिताबी मुकाबला

जोकोविच का 25वां खिताब जीतने का लक्ष्य

ऑस्ट्रेलियन ओपन के रोमांचक सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच ने जानिक सिनर को पांच सेटों के कड़े मुकाबले में हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जहाँ अब उनका सामना कार्लोस अल्काराज़ से होगा। यह खिताबी मुकाबला जोकोविच के रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब और अल्काराज़ के पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन ताज के बीच एक महत्वपूर्ण जंग होगी। जोकोविच ने यूएस ओपन 2024 के बाद से कोई ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीता है, और तब से सिनर और अल्काराज़ के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें बड़ी ट्रॉफियों से दूर रखा है। इन दोनों खिलाड़ियों ने पिछले आठ प्रमुख खिताब आपस में बाँट लिए हैं। जोकोविच ने सिनर-अल्काराज़ के बीच लगातार चौथे ग्रैंड स्लैम फाइनल को रोक दिया। अगर सिनर जीत जाते, तो वे और अल्काराज़ ओपन एरा में लगातार चार प्रमुख फाइनल में पहुँचने वाली दूसरी जोड़ी बन सकते थे, जोकोविच और राफेल नडाल के बाद, जिन्होंने विंबलडन 2011 और रोलैंड गैरोस 2012 के बीच ऐसा किया था। सर्बियाई टेनिस के दिग्गज नोवाक जोकोविच ने टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए युवा इतालवी

खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन जानिक सिनर के खिलाफ पांच मैचों की हार का सिलसिला तोड़ते हुए मेलबर्न में शुक्रवार को खेले गए पांच सेटों के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई। जोकोविच अब अपने रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब और मेलबर्न में 11वें खिताब के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। एटीपी वेबसाइट के अनुसार, सर्बियाई दिग्गज ने सिनर को एक रोमांचक मुकाबले में 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 से हराया, जो चार घंटे से अधिक समय तक चला। फाइनल में उनका एक और युवा प्रतिद्वंद्वी कार्लोस अल्काराज़ इंतजार कर रहा है, जो आखिरकार ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी पर कब्जा करने का लक्ष्य बना रहा है, एक ऐसी ट्रॉफी जो नंबर एक रैंकिंग के बावजूद उससे दूर रही है।

टेम्बा बावुमा के बयान से गौतम गंभीर को मिला समर्थन

दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के समर्थन में खुलकर बयान दिया है, जब टीम इंडिया के रेड-बॉल (टेस्ट) क्रिकेट में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उनके भविष्य पर सवाल उठे हैं। बावुमा ने कहा है कि भारत वर्तमान समय में "संकट" नहीं बल्कि "ट्रांज़िशन (बदलाव) दौर" से गुजर रहा है और इस दौरान गंभीर को समय और समर्थन देने की जरूरत है।बावुमा ने अपने कॉलम में लिखा कि भारतीय टीम की टेस्ट स्थिति को निराशाजनक स्थिति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह विकास के एक स्वाभाविक चरण का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका, 2019 के आसपास इसी तरह के बदलावों से गुज़री थी और समय के साथ बेहतर प्रदर्शन कर पाई थी, इसलिए भारत को भी धैर्य और निरंतरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।उन्होंने कोचिंग स्ट्रक्चर पर उठ रहे सुझावों की भी आलोचना की और कहा कि रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल के लिए अलग कोचिंग मॉडल की बजाय एक कोच के नेतृत्व में काम करना खिलाड़ियों के लिए अधिक फायदेमंद होता है। बावुमा के मुताबिक़, कई टीमें पहले अलग-अलग कोचिंग सिस्टम अपनाती थीं लेकिन अब एकल कोच सिस्टम ही बेहतर दृष्टिकोण साबित हो रहा है।बावुमा ने यह भी कहा कि सीमित ओवरों (वनडे और टी20) में भारतीय टीम के मजबूत संसाधन गंभीर के लिए राहत का कारण बन सकते हैं, क्योंकि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भारत ने हाल के वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है।

पाकिस्तान का नाटक जारी ; सस्पेंस बरकरार

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जर्सी लॉन्च कार्यक्रम के अचानक रद्द कर दिए जाने से देश में क्रिकेट जगत में बड़ी हलचल मच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने यह कार्यक्रम अनिवार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए टाल दिया, जिससे टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है।जर्सी लॉन्च इवेंट का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के दूसरे मैच के टॉस के बाद किए जाने की योजना थी, लेकिन आखिरी क्षण पर इसे रद्द कर दिया गया। PCB ने विस्तृत कारण नहीं बताए हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार से अंतिम मंजूरी न मिलने के कारण बोर्ड ने यह कदम उठाया है।हालाँकि पाकिस्तान ने अपने 15 सदस्यीय टीम स्क्वॉड की घोषणा कर दी है और टीम की 2 फरवरी की सुबह कोलंबो के लिए यात्रा की तैयारियां भी पूर्ण कर ली हैं, लेकिन बोर्ड ने आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है कि टीम पूरे टूर्नामेंट में भाग लेगी या केवल कुछ मैच खेलेगी।इस विवाद की पृष्ठभूमि में यह भी सामने आया है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद से ही PCB और ICC के बीच संबंधों पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सुरक्षा चिंताओं के पक्ष में बयान दिए थे, लेकिन ICC ने सुरक्षा आधार पर मैचों को स्थानान्तरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, जिससे द्विपक्षीय तनाव बना हुआ है।आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जर्सी लॉन्च कार्यक्रम के अचानक रद्द कर दिए जाने से देश में क्रिकेट जगत में बड़ी हलचल मच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने यह कार्यक्रम अनिवार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए टाल दिया, जिससे टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने इतिहास रच दिया है और 709.41 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर को पार कर लिया है। यह आंकड़ा 23 जनवरी, 2026 को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ हासिल हुआ है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी नवीनतम डेटा में सामने आया है।RBI के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (Foreign Currency Assets) भी बढ़कर 562.88 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं, जबकि स्वर्ण भंडार का मूल्य भी 123 अरब डॉलर के करीब दर्ज किया गया है। इसी के साथ विशेष आहरण अधिकार (SDRs) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सुरक्षित भंडार में भी मामूली वृद्धि देखी गई है।यह रिकॉर्ड वृद्धि वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में तेजी और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में इजाफे के कारण संभव हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उछाल भारत की बाहरी आर्थिक स्थिति के स्थिर और मजबूत होने का संकेत है, खासकर तब जब देश बजट सत्र से पहले इस उच्चतम स्तर को छूने में सफल रहा है।आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले अगस्त 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 704.89 बिलियन डॉलर पर पहुंचा था, लेकिन अब इस नवीनतम आंकड़े ने पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। हालाँकि रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव के बीच भी भंडार में वृद्धि बनी हुई है, जो भारत की वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता को दर्शाता है।आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में मुद्रा भंडार का होना देश को आयात, निर्यात और चालू खाता घाटे जैसी वैश्विक परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम बनाता है और विदेशी निवेश आकर्षित करने में भी मदद करता है।विशेष विशेषज्ञों के अनुसार, भारत का वैश्विक रिकॉर्ड स्तर पर 709 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था पर कई सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले, इतना बड़ा भंडार भारत को वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और वित्तीय संकट जैसे जोखिमों से बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने में सहायता करेगा। चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार में सोना और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, यह तेज़ी से बदलते अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की धार के बीच एक महत्वपूर्ण बफर (buffer) का काम करेगा, जिससे देश चालू खाता घाटा, आयात भुगतान और विदेशी ऋण सेवा जैसी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकेगा।दूसरे, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नोटबंदी और मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप की क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे स्थानीय मुद्रा रुपये की अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने और अचानक से विदेशी निवेश के बहिर्वाह को रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है।तीसरे, इस स्तर का भंडार वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा और भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) तथा पोर्टफोलियो निवेश आकर्षित करने में भी लाभ मिलेगा। इससे देश में रोजगार, उत्पादन और निर्यात जैसे क्षेत्रों को समर्थन मिलेगा, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।अंत में, यह भंडार "इंपोर्ट कवरेज" के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है — यानी यह दर्शाता है कि भारत लंबे समय तक बिना बाहरी सहायता के अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, चाहे तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें उच्च स्तर पर क्यों न हों। इससे आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी सकारात्मक संकेत मिलता है।

लॉन्च हुआ सुपर-प्रीमियम स्पीकर

फ्रेंच ऑडियो ब्रांड देवियालेट ने भारत में अपना नवीनतम हाई-एंड वायरलेस स्पीकर फैंटम अल्टीमेट ऑपेरा डी पेरिस संस्करण लॉन्च किया। इसे मीडिया में पहले ही "ऑडियो का रोल्स रॉयस" कहा जा चुका है।स्पीकर में 1,100 वाट तक की शक्ति और 14 हट्ज़ से 35 किलोहट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी है, जो हर ध्वनि को गहराई और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करता है। इसमें वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3, एयरप्ले और स्पॉटिफ़ाई/टाइडल कनेक्ट जैसी सुविधाएँ मौजूद हैं। देवियालेट ओएस (DOS3) सॉफ़्टवेयर के जरिए संगीत और सिनेमा मोड के साथ ऑडियो को कस्टमाइज़ किया जा सकता है।स्पीकर में स्मार्ट कनेक्टिविटी और कमरा-विशिष्ट ट्यूनिंग विकल्प दिए गए हैं, जिससे उपयोगकर्ता अपने कमरे के आकार और ध्वनि वातावरण के अनुसार साउंड सेटिंग बदल सकते हैं। यह मॉडल होम थिएटर, लाइव स्ट्रीमिंग और प्रीमियम पार्टी सेटअप के लिए भी उपयुक्त माना जा रहा है।डिज़ाइन:ऑपेरा डी पेरिस संस्करण में फ्रेंच कलाकारों द्वारा हाथ से लगाई गई गोल्ड लीफ डिटेलिंग है, जो इसे सिर्फ़ स्पीकर नहीं बल्कि एक कलाकृति बनाती है। इसकी लक्ज़री फिनिश और प्रीमियम मैटेरियल इसे घर की सजावट में भी आकर्षक बनाते हैं।

स्टॉप लॉस लगाना बेहद ज़रूरी

ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बढ़ा, स्टॉप लॉस लगाना बेहद ज़रूरीआम बजट पेश होने के दिन शेयर बाज़ार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, और ऐसे माहौल में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। बाज़ार विशेषज्ञों ने साफ चेतावनी दी है कि इस दिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि बजट घोषणाओं के दौरान बाज़ार की चाल अक्सर अनुमान से परे होती है।विश्लेषकों के अनुसार, बजट भाषण के दौरान टैक्स, खर्च, सब्सिडी, विनिवेश या किसी सेक्टर विशेष से जुड़ी घोषणाएँ अचानक सेंटीमेंट बदल देती हैं। इसका सीधा असर निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे प्रमुख इंडेक्स पर पड़ता है, जिससे ऑप्शन प्रीमियम में तेज़ उछाल या गिरावट आती है। कई बार कुछ ही मिनटों में बड़े मूवमेंट देखे जाते हैं, जिससे बिना सुरक्षा के लिए गए पोज़िशन में भारी घाटा हो सकता है।ऑप्शन ट्रेडिंग में खासकर शॉर्ट पोज़िशन रखने वाले ट्रेडर्स के लिए खतरा और अधिक होता है। वोलैटिलिटी बढ़ने पर प्रीमियम तेजी से बढ़ सकता है और मार्जिन कॉल की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि हर ट्रेड के साथ पहले से तय स्टॉप लॉस और रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए।ब्रोकर कंपनियों का भी कहना है कि बजट डे पर ट्रेडिंग वॉल्यूम सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक होता है, लेकिन इसी के साथ अनिश्चितता भी चरम पर रहती है। अनुभवी ट्रेडर्स इस दिन छोटे साइज में ट्रेड करना या सिर्फ दिशा स्पष्ट होने के बाद पोज़िशन बनाना पसंद करते हैं।मार्केट एक्सपर्ट्स का साफ संदेश है — "मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है।" यानी व्यक्तिगत अनुमान, न्यूज़ या अफवाहों से ज़्यादा असर असल घोषणाओं और बड़े निवेशकों की प्रतिक्रिया का होता है। इसलिए भावनाओं में आकर ओवरट्रेडिंग करने से बचना और पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देना ही समझदारी मानी जा रही है।बजट डे पर मुनाफ़े के अवसर जरूर होते हैं, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। ऐसे में अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और स्टॉप लॉस का पालन ही सफल ट्रेडिंग की कुंजी माना जा रहा है।

हैरान करने वाला रिकॉर्ड: 72 घंटे तक पेड़ से चिपकी रही युवती

केन्या की रहने वाली 22 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता ट्रूफेन मुथोनी ने अपने इस कारनामे से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है। इस कारनामे के तहत ट्रूफेन मुथोनी लगातार 72 घंटे तक एक पेड़ को गले लगाकर खड़ी रहीं।

साई पलवी को तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार बेस्ट अभिनेत्री का सम्मान

दक्षिण भारतीय सिनेमा की चर्चित और प्रतिभाशाली अभिनेत्री साई पलवी को तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार में बेस्ट अभिनेत्री के सम्मान से नवाज़ा गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 2016 से 2022 के बीच की फिल्मों के लिए घोषित राज्य फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत प्रदान किया गया, जिसमें साई पलवी को 2022 के लिए उनके उत्कृष्ट अभिनय के कारण चुना गया।उन्हें यह सम्मान फिल्म Gargi में निभाई गई दमदार भूमिका के लिए मिला है। इस फिल्म में साई पलवी ने एक ऐसी युवती का किरदार निभाया था जो कठिन सामाजिक और कानूनी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है। उनके अभिनय को समीक्षकों ने संवेदनशील, संतुलित और बेहद प्रभावशाली बताया था। फिल्म में भावनात्मक दृश्यों में उनकी सशक्त अभिव्यक्ति को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने सराहा।पुरस्कार मिलने पर साई पलवी ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए "बहुत महत्वपूर्ण और भावनात्मक" है। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम, निर्देशक और दर्शकों का आभार जताते हुए कहा कि ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना उनके करियर का सबसे संतोषजनक पहलू है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पुरस्कार उन्हें भविष्य में और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएँ निभाने की प्रेरणा देगा।साई पलवी लंबे समय से ऐसी फिल्मों का चयन करने के लिए जानी जाती हैं जिनमें मजबूत कहानी और भावनात्मक गहराई होती है। उन्होंने अपने करियर में कई व्यावसायिक प्रस्तावों को ठुकराकर कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि वे सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में पहचानी जाती हैं। सिनेमा की विविध प्रतिभाओं को पहचान मिली।

लखनऊ में 7 भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण

राजधानी लखनऊ को भव्य प्रवेश द्वारों के साथ एक आधुनिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

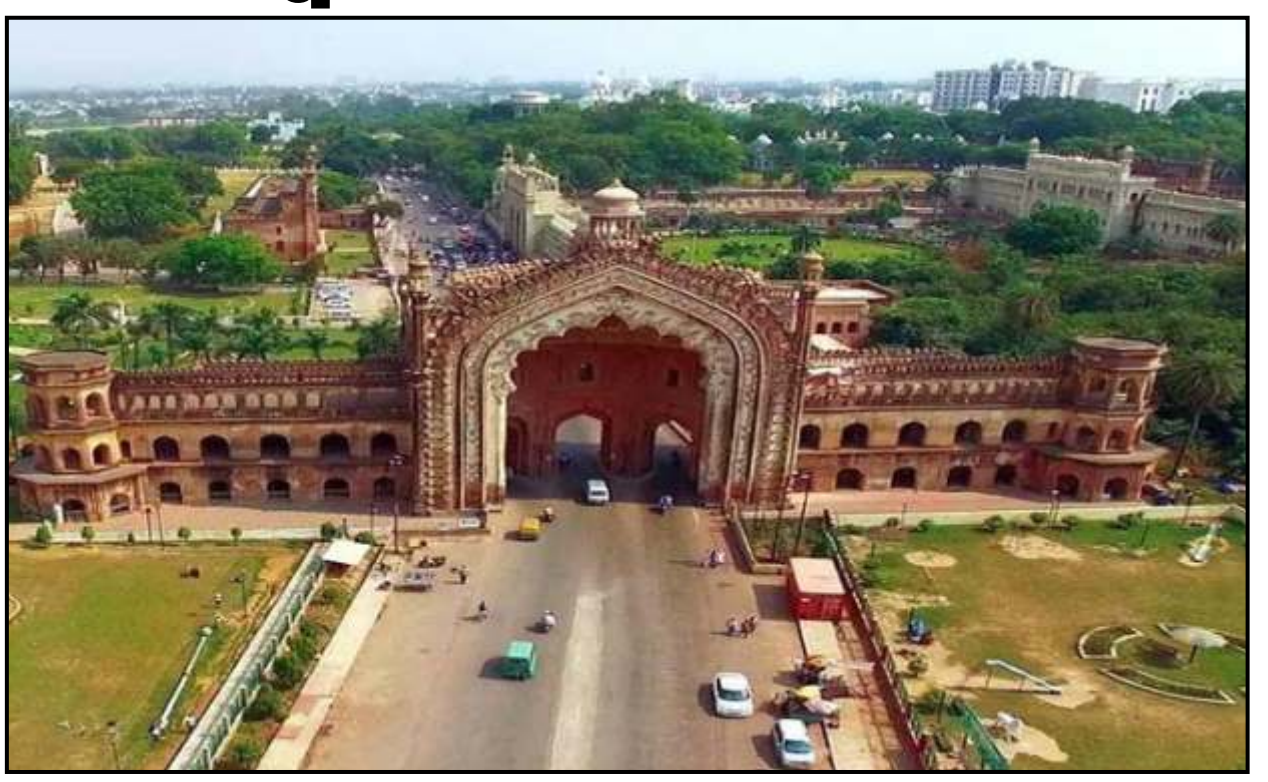

लखनऊ, 31 जनवरी — उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों का निर्माण किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शहर को एक विशिष्ट पहचान देना और राज्य की समृद्ध विरासत को उजागर करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक में सभी सात प्रमुख प्रवेश मार्गों पर प्रवेश द्वार बनाने के निर्देश जारी किए हैं।इन प्रवेश मार्गों में शामिल हैं लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, नैमिषारण्य, हस्तिनापुर, मथुरा और झांसी की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों पर विकसित किए जाने वाले द्वार, जो संबंधित दिशा की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को दर्शाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लखनऊ में प्रवेश करते ही यहां की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत का अनुभव होना चाहिए।प्रवेश द्वारों के डिज़ाइन और नामकरण पर भी विचार किया गया है। वक्तव्य के अनुसार प्रत्येक मार्ग पर ऐसे प्रतीकात्मक द्वार विकसित होंगे जो उस मार्ग से जुड़े इतिहास और संस्कृति को प्रतिबिंबित करेंगे, जैसे 'संगम द्वार', 'नंदी द्वार', 'सूर्य द्वार' आदि, ताकि शहर में प्रवेश करते ही लोगों को एक विशिष्ट सांस्कृतिक स्वागत अनुभव मिले।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इन द्वारों के निर्माण में भारतीय पारंपरिक वास्तुकला, शिल्पकला, प्रकाश व्यवस्था और हरित परिदृश्य का समावेश किया जाएगा, जिससे ये न केवल सौंदर्यपूर्ण हों बल्कि अर्थपूर्ण भी बनें। निर्माण के लिए कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) फंड के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि कार्यों का समन्वय और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।इस पहल से लखनऊ को न केवल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रवेश द्वारों वाला शहर बनने का अवसर मिलेगा, बल्कि यात्रियों और आम नागरिकों को राज्य की विविधता और विरासत का पहला आकर्षक अनुभव भी प्राप्त होगा।इसके अलावा, सरकार ने प्रवेश द्वारों के नाम और थीम पर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि हर द्वार उस मार्ग से जुड़ी धार्मिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक पहचान को प्रदर्शित कर सके। उदाहरण के लिए, प्रयागराज मार्ग पर 'संगम द्वार' बनाया जाएगा, जो त्रिवेणी संगम और महाकुंभ की परंपरा को दर्शाएगा, जबकि अयोध्या मार्ग पर 'सूर्य द्वार' रहने की संभावना है, जो सूर्यवंशी और रामायण की सांस्कृतिक भावना को उजागर करेगा। इसी तरह मथुरा मार्ग पर 'कृष्ण द्वार', झाँसी मार्ग पर 'शौर्य द्वार' और नैमिषराय मार्ग पर 'व्यास द्वार' जैसे प्रतीकात्मक नामों पर विचार किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल शहर में आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करना है, बल्कि आने-वाले यात्रियों और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की विविध सांस्कृतिक विरासत का पहला अनुभव तुरंत प्रदान करना है।प्रवेश द्वारों के निर्माण की अनुमानित समयसीमा पर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सभी **सात प्रवेश द्वारों का निर्माण अगले 12 से 18 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है। प्रारंभिक योजना के तहत पहले तीन द्वारों (प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी मार्ग) का निर्माण अगले 6 से 8 महीनों में शुरू होने की संभावना है, जबकि शेष चार द्वारों (नैमिषारण्य, हस्तिनापुर, मथुरा और झाँसी मार्ग) का कार्य क्रमशः अगले चरणों में पूरा किया जाएगा।

प्रदेश में ठंड की वापसी, आधे हिस्से में घना कोहरा, बूंदाबांदी से बढ़ी ठिठुरन

यूपी में बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड फिर लौट आई है। कई जिलों में घना कोहरा छाया है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है। बर्फीली हवाओं से तापमान गिरा है। यूपी में बारिश और ओले गिरने के बाद ठंड फिर लौट आई है। शनिवार सुबह से लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, गाजियाबाद समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया है। कई जिलों में विजिबिलिटी 10 मीटर तक है। बर्फीली हवाओं से तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सुबह-शाम गलन बढ़ गई है। सड़कों पर सन्नाटा है। गाड़ियों से निकले लोगों के हाथ सुन्न हो जा रहे हैं। लोग गर्म कपड़े पहनकर और अलाव सेंककर ठंड से बचते नजर आ रहे हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 31 जनवरी तक कोहरे में बढ़ोतरी होगी और कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है। फरवरी के पहले सप्ताह में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से एक से तीन फरवरी के बीच पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है और कोहरे से राहत मिलेगी। चार फरवरी से तापमान में फिर हल्की गिरावट आने के आसार हैं। शुक्रवार को 8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ बुलंदशहर सबसे ठंडा रहा। वहीं 21.9 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ आगरा सबसे गर्म रहा।

योगी ने जमीन पर बैठकर भजन सुना, दीप दान किया:

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद स्मारक स्थल, महात्मा गांधी मार्ग पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल हुए। उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जमीन पर बिछाए गए आसन पर बैठकर लोगों के साथ भजन सुना। गोमती नदी में दीप दान किया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था। वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे, वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे। रघुपति राघव राजा राम सहित महात्मा गांधी के अन्य पसंददीदा भजनों को सुना। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्री राकेश सचान, मेयर सुषमा खर्कवाल, विधायक जय देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहीं। कार्यक्रम में शामिल बसंत लाल वर्मा ने कहा- आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। हम लोग एक साथ एकत्रित होकर उन्हें याद कर रहे हैं। लाठी लेकर चलने वाले दुबले-पतले महात्मा गांधी के पीछे दुनिया के हजारों लोग एक साथ चल देते थे। आज उनकी फिर जरूरत है। दुनिया युद्ध की विभिषिका में इस समय पड़ी हुई है, उनको बचाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। सत्य और अहिंसा का रास्ता।

दफ्तर का टाइपिस्ट निकला करोड़पति, 4 जिलों में 17 करोड़ की संपत्ति का खुलासा

लखनऊ: जिला पूर्ति अधिकारी मऊ के तत्कालीन टाइपिस्ट गगन कुमार सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी में 17 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों का खुलासा हुआ है, जबकि उसकी आय जांच के समय तक सिर्फ एक करोड़ रुपये थी। छापेमारी के दौरान जांच टीम को उसके चार मकानों, एक ईंट भट्ठे का पता चला। इसके साथ ही 44 संपत्तियों के बैनामे से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। शासन के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ हुई प्रारंभिक जांच में उसकी आय और संपत्ति में भारी असंगति पाई गई थी। शासन को भेजी गई खुली जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई। अनुशंसा स्वीकार करते हुए शासन ने मुकदमा दर्ज करवाया।

लखनऊ में सरेआम फायरिंग, रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी गंभीर

यूपी के लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद हैं. उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है. बीते दिनों दबंगों ने एक कारोबारी के दोनों पैरों पर THAR कार चढ़ा दी थी और कारोबारी को कुचलने की कोशिश की थी. वहीं, अब एयर फोर्स से रिटायर्ड हुए अधिकारी को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल अधिकारी को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. मामला सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के शॉपिंग स्क्वायर-2 कॉम्प्लेक्स का है। यहां 60 साल के रिटायर्ड अफसर अवधेश कुमार पाठक अपनी पत्नी के साथ एक रेस्टोरेंट का संचालन करते हैं. घटना शुक्रवार रात उस समय हुई जब रेस्टोरेंट में सामान्य गतिविधि चल रही थी. ग्राहक मौजूद थे और स्टाफ अपने काम में व्यस्त था. इसी दौरान दो संदिग्ध युवक अंदर दाखिल हुए.

KGMU धर्मांतरण केस में बड़ा ट्विस्ट, गवाह ही निकला मास्टरमाइंड का साथी

लखनऊ के केजीएमयू महिला रेजीडेंट डॉक्टर धर्मांतरण मामले में गवाह शारिक खान को गिरफ्तार किया गया है. शारिक धर्मांतरण के बाद महिलाओं के नए नाम पर जाली दस्तावेज तैयार करवाता था. उसके मोबाइल से भी कई डिजिटल सबूत मिले हैं. उत्तर प्रदेश में लखनऊ के केजीएमयू महिला रेजीडेंट डॉक्टर धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. धर्मांतरण का गवाह बनने वाले शारिक खान को लेकर जांच में सामने आया है कि वो गवाह ही नहीं था, बल्कि धर्मांतरण के बाद महिलाओं के नए नाम पर जाली दस्तावेज भी तैयार करवाता था.

आरोपी डॉ. रमीज के बेहद करीबी और धर्मांतरण का गवाह बनने वाले शारिक खान की शुक्रवार (30 जनवरी 2026) को कोर्ट में पेशी थी. इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस मामले में अब तक चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि धर्मांतरण कराने वाला काजी उम्र और बीमारी का हवाला देकर अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है.

यूपी स्टार्टअप फंड के ₹1000 करोड़ से इनोवेशन को मिला मजबूत आधार

उत्तर प्रदेश में नवाचार (इनोवेशन), स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति देने के लिए योगी सरकार द्वारा गठित 1000 करोड़ का यूपी स्टार्टअप फंड स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए मजबूत सहारा बनकर उभरा है. इस फंड के माध्यम से अब तक 325 करोड़ की राशि स्टार्टअप्स को सीधे सहायता के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है, जिससे प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को उल्लेखनीय मजबूती मिली है. प्रदेश में वर्तमान में 19 हजार से अधिक स्टार्टअप्स को डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त है, जिनमें 9600 से अधिक महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप शामिल हैं. यह आंकड़ा प्रदेश में महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है. प्रदेश में अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं. इन केंद्रों पर अब तक 27.18 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं. यूपी स्टार्टअप फंड के माध्यम से 48 यूपी आधारित स्टार्टअप्स को सीधे फंडिंग भी प्रदान की गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं. यह पहल उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और प्रदेश के युवाओं को नवाचार के जरिए आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है.स्टार्टअप के शुरुआती दौर की आर्थिक चुनौतियों को कम करने के लिए सरकार की भरण-पोषण भत्ता योजना के तहत 115 आवेदन स्वीकृत कर 2.46 करोड़ की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 97 लाख का भुगतान किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त 566 इंसेंटिव आवेदन स्वीकृत कर 32 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है. सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल प्रोटोटाइप विकास, सीड फंडिंग, मार्केटिंग सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए किया जा रहा है, जिससे नवाचार आधारित स्टार्टअप अपनी व्यावसायिक योजनाओं को तेजी से वास्तविक रूप दे पा रहे हैं।योगी सरकार इस योजना के माध्यम से प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में उभारने का लक्ष्य रखती है और आशा है कि इससे रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले समय में इस फंड के दायरे को और प्रभावी बनाने के लिए मेंटरशिप नेटवर्क, निवेशकों से जुड़ाव और जिला स्तर पर इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति को लेकर विवाद, स्थानीय प्रतिक्रिया बंटी

वाराणसी हिन्दुओं की धार्मिक नगरी के रूप में चर्चित वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है. वह 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं. प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से वाराणसी में विकास की कई परियोजनाएं चल रही हैं. इसी कड़ी में ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट का भी पुनर्विकास किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का दावा है कि इसके लिए पहले पुराने ढांचों को तोड़ा गया है. इस तोड़-फोड़ को लेकर स्थानीय लोग नाराज़ भी हैं. कई लोगों का आरोप है कि वहां मौजूद इंदौर के पूर्व राजघराने की अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति भी टूट गई है. लेकिन वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी इससे इनकार करते हैं. उनका कहना है कि मूर्ति सुरक्षित रखी गई है, जिसे बाद में स्थापित कर दिया जाएगा. अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति टूटने के दावों के बाद वहाँ विरोध प्रदर्शन भी हुए. पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया. विरोध प्रदर्शन में शामिल काशी के पाल समाज के अध्यक्ष महेंद्र पाल कहते हैं, "अहिल्याबाई होल्कर हम लोगों की पूर्वज रही हैं और वो पाल समाज की महिला थीं." उन्होंने दावा किया, "हम लोग मौक़े पर पहुंचे थे और तोड़-फोड़ देखी थी. जेसीबी लगाकर मूर्ति को तोड़ा जा रहा था. इसलिए जब उनकी मूर्ति खंडित की गई, तो हमने विरोध किया. लेकिन पुलिस ने हमें वहाँ जाने नहीं दिया." वाराणसी में चौक के तरफ़ से कई संकरी गली को पार करने के बाद मणिकर्णिका घाट पर पहुंचा जा सकता है कई लोग पूजा पाठ के लिए आते हैं. गंगा में स्नान करने के बाद पूजा करते हैं.

वैसे तो वाराणसी में 80 से अधिक घाट हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट को धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी घाट के पुनर्विकास के लिए काम शुरू हुआ है. लेकिन मूर्ति टूटने के दावे के बाद विवाद खड़ा हो गया है. विवाद के बाद घाट को चारों तरफ़ से घेर दिया गया है. यहां पुलिस का पहरा है और किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है. गंगा नदी की तरफ़ से ये दिखता है कि पूरे इलाक़े को मिट्टी और बालू से ढक दिया गया है. कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि मशीनों की तोड़-फोड़ में कई 'मणियां' खंडित हो गई हैं. इन लोगों का कहना है कि पुनर्विकास के नाम पर प्राचीन परंपराओं और स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है.

अमृत योजना में घोर लापरवाही, मुझे धरातल पर काम चाहिए: आशुतोष शुक्ला

उन्नाव। अमृत योजना को लेकर जल निगम के अधिकारियों की घोर लापरवाही से लोगों को शुद्ध पानी तो मिला ही नहीं जो सड़कें थी वह भी पाइप लाइन डालने के लिए खोद डाली गई, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भी कठिनाई का सामना करना पड़ है।

ग्रामीणों की शिकायत पर भगवंत नगर विधायक ने जल निगम के अधिशासी अभियंता और अमृत योजना का काम कर रही कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को मौके पर बुलाया।

लापरवाही की हकीकत दिखाते हुए कहा कि मुझे धरातल पर काम चाहिए मैं उनमें नहीं हूं जो चाय काफी पीकर चला जाऊं, मुझे धरातल पर काम चाहिए अगर काम में लापरवाही जारी रही तो अब मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी देकर कार्रवाई कराऊंगा। गुरुवार को भगवंतनगर क्षेत्र भ्रमण पर निकले थे। सुपासी व बंड हमीरपुर के विकास कार्यों का जायजा लिया, इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें जल निगम द्वारा खोदी गई सड़कें और उनकी मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति किए जाने तथा नला ें में पानी न आने की जानकारी दी। इस पर विधायक ने अधिशासी अभियंता जल निगम को मौके पर बुलाया ग्रामीणों की शिकायत बताते हुए उनसे सही काम न करने पर सवाल किया तो अधिकारी बगले झांकते हुए उनको समझाने का प्रयास करने लगे इस पर विधायक का पारा चढ़ गया उन्होंने कहा कि मुझे धरातल पर काम चाहिए। जहां आपने कराया हो चलो वहां दिखा दो। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम को सीधे निशाने पर लेते हुए जमकर क्लास ली। उन्हें चेतावनी दी कि अगर काम सही नहीं हुआ तो अब मुख्यमंत्री को जानकारी देकर कार्रवई कराऊंगा। विधायक द्वारा अमृत योजना में घोर अनियमितता और लापरवाही को लेकर जल निगम के अधिकारियों की क्लास लेने का वीडियो भी इंटर नेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। विधायक ने बताया कि सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार पूरा पैसा दे रही है। उसके बाद भी वह निर्माण नहीं करा रहे हैं। पानी तो अब तक मिला ही नहीं।

आईआईटी बीएचयू में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

वाराणसी. कर्मचारियों में सेवा भाव के संदेश के व्यापक प्रसार के उद्देश्य से राष्ट्रीय कर्मयोगी वृहद पैमाने पर जन सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी में शुक्रवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्रीनिवास देशपांडे पुस्तकालय के प्रथम तल स्थित पुस्तकालय सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर इंचार्ज (प्रशासन) प्रोफेसर रंजीत महंती एवं संस्थान के कुलसचिव श्री सुमित कुमार बिस्वास ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रोफेसर इंचार्ज (प्रशासन) प्रोफेसर रंजीत महंती ने कहा कि राष्ट्रीय कर्मयोगी वृहद पैमाने पर जन सेवा कार्यक्रम भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य नियम-आधारित प्रणाली से भूमिका-आधारित एवं दक्षता-संचालित क्षमता निर्माण की दिशा में संक्रमण के माध्यम से सिविल सेवाओं में व्यापक रूपांतरण लाना है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिक उत्तरदायी, दक्ष एवं सेवा-उन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्थान के कुलसचिव श्री सुमित कुमार बिस्वास ने अपने संबोधन में कहा कि यह कार्यक्रम निरंतर अधिगम, कौशल उन्नयन तथा सभी स्तरों के अधिकारियों में सकारात्मक व्यवहारिक परिवर्तन पर केंद्रित है।

मांगों को लेकर आशा वर्करों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

कानपुर. उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आशा वर्करों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। आशा वर्करों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करके जमकर नारेबाजी की। जमीन पर बैठककर धरना प्रदर्शन किया। 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन आशा वर्करों ने मजिस्ट्रेट ज्वाला प्रसाद को सौंपा। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। रामआसरे पार्क से जुलूस निकालकर आशा वर्कर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंची। आशा वर्करों ने उत्पीड़न बंद करो और उनको नियमित करो आदि नारे लगाए। कहा कि बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान करें, सरकारी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत करें, आशा को ईपीएफ, ईएसआई का सदस्य बनाया जाए, सेवानिवृतति पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, 50 लाख का जीवन बीमा किया जाए, न्यूनतम वेतन लागू होने तक आधारभूत मानदेय, भ्रमण यात्रा भत्ता दिलाया जाए।

भाजपा विधायक के समर्थकों का हंगामा, मंत्री स्वतंत्र देव के काफिले पर घेराव, झड़प

जिले में सड़कों की बदहाली से नाराज विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला बीच सड़क पर रोककर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई, जिससे कलेक्ट्रेट मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

महोबा जिले में एक दिवसीय महोबा भ्रमण पर आए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौटते समय भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत और उनके समर्थकों ने काफिला रोक लिया। इस दौरान विधायक व उनके समर्थकों ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की बदहाली बताई। विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई।

बताया जा रहा है कि शहर के रामश्री महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद मंत्री का काफिला लौट रहा था। तभी कलक्ट्रेट मार्ग पर बड़ी संख्या में भाजपा विधायक व समर्थकों ने काफिला रोका। सीओ सदर अरुण कुमार सिंह और एसडीएम शिवध्यान पांडेय ने मामले को नियंत्रण में किया। रास्ते से गाड़ी हटवाने के लिए स्वतंत्रदेव को खुद नीचे उतरकर आना पड़ा। काफिला रुकने के बाद जलशक्ति मंत्री वाहन से नीचे उतर आए। इस दौरान विधायक से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। पूरा मामला पहले से प्लानिंग के तहत माना जा रहा है। चरखारी विधायक के साथ बड़ी संख्या में पहले से ही समर्थक कलक्ट्रेट मार्ग पर पहुंच गए थे। बीच सड़क पर गाड़ियां लगाकर काफिला रोका गया। जब मंत्री गाड़ी से उतरे तो कहासुनी हुई। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए समर्थकों को सड़क से अलग कराया और काफिला आगे बढ़वाया। भाजपा विधायक के साथ बड़ी संख्या में प्रधान भी पहुंचे। जिनका कहना था कि जल जीवन मिशन से खोदी गई सड़कों की दशा खराब है, जिन्हें आजतक दुरुस्त नहीं कराया गया। साथ ही, कई गांवों में अभी तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तीन साल से समस्या बरकरार है। एसडीएम शिवध्यान पांडेय ने बताया कि विधायक के समर्थकों ने समस्या बताने के लिए जलशक्ति मंत्री के काफिले को रोका था। इसके बाद में समर्थकों को अलग कराकर काफिला आगे बढ़ाया गया। काफिला रोकने के बाद चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत और जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव के बीच बातचीत हुई। मंत्री ने कहा कि जहां कोई शिकायत है, वहां मुझे लेकर चलो। उस गांव में मैं खुद चलता हूं। 40 गांवों में कहोगे तो मैं सभी जगह चेक करने चलूंगा, मेरे साथ अफसर हैं। सभी जगह देखूंगा, लापरवाही मिलने पर अफसरों को सस्पेंड कर दूंगा। आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलिए। काफिला रोकने और झड़प के बाद जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत को अपनी गाड़ी में बैठाया। इस दौरान विधायक के समर्थकों की इंस्पेक्टर से झड़प हो गई। समर्थकों का कहना था कि पूरी बात हो जाएगी, वह तभी जाएंगे। इसी दौरान एक समर्थक बोला- आंख क्यों दिखा रहे हो, खा जाओगे क्या। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं है, बात तो हो रही है।

यूपी कैबिनेट ने दी मंज़ूरी, 11.92 लाख शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह ही कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दो दी गई है। इस फैसले से 11.92 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले को आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस फैसले से शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइया सभी लाभांवित होंगे। इस फैसले के क्रियान्वयन में 358.61 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह ही कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दो दी गई है। इस फैसले से 11.92 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले को आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस फैसले से शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइया सभी लाभांवित होंगे। इस फैसले के क्रियान्वयन में 358.61 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

मेरठ में पुलिस मुठभेड़, डकैती के दो वांछित बदमाश दबोचे गए

मेरठ जिले में पुलिस ने डकैती की एक घटना में वांछित दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को जांच के दौरान थाना किठौर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर गोलीबारी किए जाने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें एक अभियुक्त घायल हो गया। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घायल अभियुक्त की पहचान गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी निवासी मोहसिन के रूप में की है। वहीं, गिरफ्तार दूसरे अभियुक्त की पहचान मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र के मुंडाली गांव निवासी साकिब उर्फ अंडा के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 20 और 21 जनवरी की दरमियानी रात को ग्राम मुंडाली में नकदी और आभूषण लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में मुंडाली थाने में मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 30 हजार रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल और एक तमंचा तथा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

योगी आदित्यनाथ पर शंकराचार्य का पलटवार, हिंदू पहचान के प्रमाण की मांग, 40 दिन का अल्टीमेटम

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच चल रहा तनाव और विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इसकी वजह से शंकराचार्य प्रयागराज छोड़कर काशी आ गए हैं. काशी में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए प्रयागराज में अगला स्नान न करने की भी घोषणा की है. शंकराचार्य ने कहा 'जो लोग मेरे साथ स्नान करना चाहते हैं, वह काशी आ सकते हैं. 1 तारीख माघ पूर्णिमा के दिन काशी में गौ माता की जयकारों से गंगा स्नान करके अपने संकल्प को पूर्ण करेंगे. इसके साथ ही शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खुलकर जमकर हमला बोला. कहा, मुख्यमंत्री को 40 दिन का वक्त दे रहे हैं. इस दौरान अपने हिंदू होने का प्रमाण दें. यह अवधि 10 मार्च को पूरी होगा. 11 मार्च को हम यह घोषित करेंगे कि मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है या फिर नकली हिंदू, जो भगवा पहनकर कालनेमि की शक्ल में लोगों को मूर्ख बना रहे हैं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, 'अभी तक देश में एक भेद बताया जाता था. देश की राजनीतिक पार्टियों में अंतर है. व्हाट्सएप में यह जानकारी दी जाती थी कि 1966 में जो सरकार थी, वह गौ हत्या बंद नहीं करना चाहती थी. इसलिए गौ भक्तों के ऊपर उन्होंने गोली चलवाई और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और उनके संत योगियो को परेशान किया गया. लेकिन अब जब हमने इस गौ माता की हत्या बंदी की आवाज को उठाई तो हमारे सहयोग में खड़े गौ भक्तों को सरकार परेशान कर रही है.